



मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल मंडफिया के भगवान श्री सांवलिया सेठ के दरबार में 29 मई, चतुर्दशी को भंडार खोला गया। एक जून को भंडार की राशि की गणना के दूसरे चरण में एक करोड़ 27 लाख 84 हजार रुपए की राशि नकद मिली तथा 29 मई को हुई पहले चरण की गणना में 4.90 करोड़ रुपए मिले थे। अब तक 6 करोड़ रु. से ज्यादा की राशि मिल चुकी है और 100 ग्राम वजन के 20 गोल्टे विस्किट भी मिले हैं। बताया जाता है कि, मंदिर कार्यालय से प्राप्त सोना-चांदी का वजन करवाना तथा छोटे-बड़े नोटों व सिक्कों की गिनती करना अभी बाकी है। गणना मंदिर बोर्ड अध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर की देखरेख में चल रही है। बताया जाता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ मंडफिया का भंडार हर माह चतुर्दशी या अमावस्या पर खुलता है और चढ़ावे में आए नोटों व सोने-चांदी की गणना होती है। यह प्रक्रिया 4-5 दिनों तक चलती है।

## ‘यह मनी लॉण्डरिंग...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी परिवार की 86 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

कांग्रेस ने कहा कि यह प्रकरण ऋण को इक्विटी में बदलने, ताकि कर्मचारियों को वेतन जैसी बकाया राशियों का भुगतान किया जा सके से संबंधित था। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार महंगाई जैसे “असली मुद्दों” से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। सिंचनी ने कहा कि ई.डी.ने उक्त केस 2015 में बंद कर दिया था, लेकिन सरकार ने संबंधित अधिकारियों को हटा दिया, नये अधिकारी लगाये तथा उसी केस को फिर से खोल दिया।

अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी प्रोवेन्शन ऑफ मनी लॉण्डरिंग एक्ट (पी.एम.एल.ए.) की क्रिमिनल धाराओं के अंतर्गत, उनके बयान रिकॉर्ड करना चाहती है।

नैशनल हैरल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) तथा मालिक यंग इंडियन प्रा. लिमिटेड हैं। यह केस धोखाधड़ी, साजिश तथा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) के अधिग्रहण में यंग इंडियन प्रा.लि. द्वारा किये गये क्रिमिनल न्याय-भंग/विश्वास भंग (बीच ऑफ ट्रस्ट) से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.ए.) नैशनल हैरल्ड का संचालन करती थी।

इस केन्द्रीय जांच एजेंसी ने, जांच पड़ताल के एक हिस्से के रूप में, हाल ही में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पवन बंसल से पूछताछ की थी। अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस नेताओं तथा गांधी परिवार से

पूछताछ किया जाना जांच पड़ताल का हिस्सा है ताकि शेयर होल्डिंग के पैटर्न, वित्तीय लेनदेन तथा यंग इंडियन एवं ए.जे.एल.के प्रमोटर्स की भूमिका को समझा जा सके।

एजेंसी ने भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा 2013 में दायर की गयी एक प्राइवेट क्रिमिनल शिकायत के आधार पर, पीएमएलए की क्रिमिनल धाराओं के तहत एक नया केस दर्ज किया है। इस नये केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा अन्य पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने छल-कपट एवं धोखाधड़ी की तथा यंग इंडिया के साथ मिलकर पैसे का दुरुपयोग किया तथा 50 लाख रुपये की रिश्तत देकर उस 90.25 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के अधिकार प्राप्त कर लिये जो ऐसे सिप्टेड जर्नल्स लिमिटेड पर कांग्रेस का कर्ज था।

इस प्रकरण में अभी तक कोई एफआइआर दर्ज नहीं हुई है तथा यह मुकदमा दिल्ली की अदालत में अब भी लंबित है। सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी इस केस में जमानत ले चुके हैं। सिंचनी ने कहा कि ईडी ने इस मामले में पीएमएलए जांच शुरू कर दी है, जो “गैर कानूनी” है।

सिंचनी ने आगे कहा कि ए.जे.एल.का फर्जी मुद्दा भाजपा के प्रचार तंत्र की एक कोशिश मात्र है ताकि लोगों का ध्यान महंगाई, गिरती हुई जीडीपी, सामाजिक बेचंगी एवं अशांति, देश का सामाजिक विभाजन के विभिन्न प्रकार के जबरदस्त मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया, मोड़ा तथा भटकया जा सकें। यह सब एक मिश्रण में आपके सामने प्रदर्शित करूंगा।

## ‘बसपा के दल-बदलू विधायकों को वोट देने से रोका जाए’

जयपुर, 1 जून। बसपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी को पत्र लिखकर अपील की है कि, बसपा से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में आये विधायकों को राजस्थान चुनाव में वोट डालने से रोका जाये।

बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि, 2018 में बसपा के सिम्बल पर 6 विधायक चुनाव जीतकर आये थे और उन्होंने असंवैधानिक तरीके से बसपा का

■ **बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने विधानसभा स्पीकर डॉ. सी.पी. जोशी को पत्र लिखकर अपील की है कि बसपा से असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में आए विधायकों को राजस्थान चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।**

कांग्रेस में विलय कर दिया था। इन विधायकों का यह कृत्य संविधान विरुद्ध है और दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि, इन 6 विधायकों राजेन्द्र गुड़ा, लाखन सिंह,दीपचंद खेरिया, संदीप यादव, जोगेन्द्र सिंह अवाणा व वाजिब अली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलबदल विरोधी कानून की अवमानना का मामला चल रहा है, शीघ्र ही उस पर फैसला होने वाला है। उन्होंने कहा कि, इन 6 विधायकों को राजस्थान चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।

## दिल्ली सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। अदालत ने कहा दिल्ली सरकार पिछले तीन वर्षों से “दिल्ली हैथ विल, 2019” लागू करना चाहती है, परन्तु आज तक यह कानून तैयार नहीं हो पाया है। अदालत का दिल्ली सरकार को सुझाव है कि जब तक “दिल्ली हैथ विल” 2019” को पूरी तरह तैयार कर लाया नहीं कर दिया जाता, तब तक केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पारित “क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट” को ही दिल्ली में लागू क्यों नहीं कर दिया जाता।

जैसा कि विदित है “क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट” केन्द्र सरकार द्वारा पारित कानून है, जो कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में अक्षरशः लागू किया

है। इस कानून में पैथ लैबों की तीन श्रेणियों में बांटा गया है, “एडवांस, मीडियम और बेसिक”। इस कानून में तीनों श्रेणियों को लैबों में कौन-कौन से टेस्ट किये जा सकते हैं इसकी जानकारी भी दी गई है और यह भी बताया गया है कि यह टेस्ट किस लेवल तक प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में किये जा सकते हैं। सुपीयो केर के आदेश अनुसार भी “एडवांस” और “मीडियम” लैबों में एम.डी. पैथोलॉजिस्ट ही लैब के टेस्ट रिपोर्ट हस्ताक्षरित कर सकते हैं।

न्यायाधीश मनमोहन प्रीतम सिंह अरोड़ा ने बिजाऊ कुमार मिश्रा तथा अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं और मामले की अगली तारीख 17 अक्टूबर तक तय की है।

डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि देश के इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 2014 में नरेन्द्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री के रूप में आगमन से एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सुंदर सनातन देश की व्यवस्था में ऐसे अनेकों अवसर आये जब देश को

सुनौतियों का मुकाबला करना करना पड़ा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक संघर्ष व बलिदान की कहानियां सबको ज्ञात हैं। उन्होंने कहा कि हम आजादी का 75 वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश में आजादी के आंदोलन के दौरान व उसके बाद की व्यवस्था में एक मिथक था, धरणा थी, कि देश को आजादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई। ऐसा प्रचारित भी किया गया। इसके बाद यह कहा गया कि देश पर शासन करने का हक कांग्रेस को है, उसके बाद यह स्थापित किया गया कि कांग्रेस पार्टी में भी कोई शासन कर सकता है तो वह नेहरू-गांधी खानदान कर सकता है, 75 वर्षों की आजादी में लगभग 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और एक खानदान विशेष ने देश पर शासन किया। कहने को कांग्रेस का शासन लोकतांत्रिक था, लेकिन उनके हिस्से में आपातकाल भी था, यातनायें थी, प्रतिबंध भी थे। इसी तरह बार-बार लोकतंत्र व संविधान की बात करने वाले

सामान्य व्यक्ति के बैंक के खाते नहीं थे, आज आपको आसान लगता होगा, बैंक खातों से क्या परिवर्तन होता होगा, यह भी आपने देखा है। 45 करोड़ जनघन के खातों ने भारत की जनता को ताकत दी है और भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी है।

उन्होंने कहा कि आज भारत की शत प्रतिशत आबादी के पास गैस कनेक्शन है, और 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला के हैं, जिनसे माता-बहनों को धुंसे से आजादी दिलाई है। यह बुनियादी बदलाव की बड़ी शुरुआत थी।

## गजेन्द्र सिंह व तोमर चुनाव प्रभारी

जोधपुर 1 जून (का.सं।) भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। भाजपा जोधपुर समूह मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह ने एक आदेश जारी कर राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आगामी राजस्थान चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं।

जोधपुर सांसद एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को राजस्थान चुनाव के लिए हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय कृषि मंत्री एम.एस. तोमर को राजस्थान में राजस्थान चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। जो किशन रेड्डी को कर्नाटक और केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र में राजस्थान चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है।

■ **राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि, रघु शर्मा ने कहा था कि, 2023 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस 10-15 सीटों पर सिमट जायेगी।**

■ **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 8 साल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया की प्रेस वार्ता।**

कांग्रेस के लोगों के माथे पर वो कलंक भी था, जिसमें 100 भी ज्यादा बार चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर दिया गया। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। उन्होंने कहा कि इतने बड़े लोकतंत्र में उन माता-बहनों की बिडंबना देखिये जो अंधेरा होने का इंतजार करती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने इस पीड़ा को समझा और देश में 10 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हुये, यह बदलाव की पहली शुरुआत थी।

# ‘मुख्यमंत्री जी गर्भ के बच्चे की उम्मीद में गोद वाले को छोड़ना बंद कीजिए’

## मोहन प्रकाश बोले, कांग्रेस के मूल वोट बैंक को छोड़कर ऐसे लोगों को सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं, जो वोट बैंक नहीं हैं

जयपुर, 1 जून (का.प्र.)। उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर में आयोजित दो दिवसीय एक्शन टेकन कैम्प में नेताओं के निशाने पर सरकार और अधिकारियों की कार्यशैली नेताओं के निशाने पर रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप गर्भ वाले बच्चे की उम्मीद में गोद वाले को छोड़ना बंद कीजिए।

कांग्रेस का मूल “वोट बैंक” है, हम उसकी चिंता नहीं करते, उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देते। इनकी जगह ऐसे लोगों को सत्ता में भागीदारी देते हैं जो

■ **खाचरियावास बोले, जनता का काम अटकाने वाले अफसरों का इलाज जरूरी।**

वोट बैंक नहीं है। यह गोद वाले बच्चे को छोड़कर गर्भ वाले की चिंता करने की तरह है। इससे पार्टी का हित नहीं होगा।

मोहन प्रकाश ने आगे कहा कि कांग्रेस कोई प्रदर्शन करती है तो वहां चंद नेता रहते हैं। इन प्रदर्शनों से जनता नहीं जुड़ पाती। महंगाई सहित कई मुद्दे पर जनता में मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री

गांधीवादी हैं, लेकिन भाजपा आरएसएस के कुछ नेता माहौल खराब करते हैं। उनका इलाज करने के लिए लोकल नेताओं को ताकत देना जरूरी है।

मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जनता के काम अटकाने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने का सुझाव देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में कई अफसर रोड़ा अटका रहे हैं। उनका इलाज करना जरूरी है।

बाहर आकर खाचरियावास बोले कि मैंने आज बैठक में बोला है कि कई अफसर महान हैं। जो प्रशासन शहरों के संग अंधियार में पड़े बांटे में भी लागू बन रहे हैं। बेवजह फाइलें घुमा कर डिले कर रहे हैं। अब जनता की पट्टी से जुड़ी

फाइलें घुमाने वाले अफसरों को घुमाने का वक्त आ गया है। अफसरशाही का रवैया ठीक नहीं है। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस नेता मनोबल उंचा रखें और ग्रांडेड तक सरकार के काम को पहुंचाएं। कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊपर रखने के लिए सबको साथ लेकर जनता में एकजुटता से मैसजे देना होगा।

इससे पहले शिविर की शुरुआत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चिंतन शिविर के फैसलों को धरतल पर लागू करने पर नेताओं के सुझावों को सी फील्ड लागू करना संभव नहीं होगा। फाइनल फैसला एआईसीसी के स्तर पर होगा। यह कतई नहीं माना जाए कि जो कह दिया वह लागू होगा।

# ‘हमने बी.जे.पी. पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई’

## मुख्यमंत्री गहलोत ने एक दिन पहले जो तंज किया था उसका अपने तरीके से जबाब दिया पायलट ने

■ **क्या कारण है कि राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं होती, एक बार 50 और 1 बार 21 कैसे रह गए।**

■ **कहा गया जो माहौल बना है मोदी जी के आने के बाद, लेकिन इससे पहले भी हम सरकार रिपीट नहीं कर पा रहे थे।**

को दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलत की पहचान करना जानते हैं।

सचिन पायलट ने कहा कि हमारे नेताओं को टारगेट किया गया। ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या ऐसा कभी किसी ने पहले किया है। सोनिया गांधी और उनके परिवार की एसीपी सुरक्षा वापस ली गई, मुकदमे दर्ज किए गए। हमारे नेताओं को यातनाएं दी जा रही हैं, बेल लेने पर मजबूर किया जा रहा है। पिछले आठ साल में केंद्र सरकार ने हमारे नेताओं के साथ जो कुछ किया वह सबको दिख रहा है।

इससे पहले सुबह भी सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए राजस्थान में सरकार



पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं टॉक विधायक सचिन पायलट ने बुधवार को जयपुर में आयोजित कांग्रेस के “एक्शन टेकन कैम्प” को संबोधित किया।

रिपीट नहीं होने को लेकर कहा कि हम लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे एक बार सिर्फ 50 विधायक रह गए थे, एक बार 21 विधायक रह गए थे। ऐसा क्या कारण है कि जनता बहुमत देती है। हम राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। हमारी सरकार दिल्ली में रिपीट हो चुकी, असम में रिपीट हो चुकी, आंध्र में रिपीट हो चुकी। जैलौल कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती

है। राजस्थान में किन कारणों से सरकार रिपीट नहीं हो पाती है तो उन कारणों पर चर्चा भी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद सभी जगह हार के बहाने बनाए जाने की बात को लेकर भी पायलट ने कहा कि इससे पहले भी हम सरकार रिपीट नहीं कर पा रहे थे। इन कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। कार्यशाला में संकल्प भी लेंगे कि कैसे एकजुटता के साथ चुनाव

लड़ा जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो। उन्होंने कहा कि मैंने जो सुझाव दिए, मैं एआईसीसी, सोनिया गांधी को धन्यवाद देता हूँ कि उन विचारों को उन्होंने स्वीकार किया। हमारे सुझावों पर समिति बनाई। उसने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम सही समय पर सही कदम उठाकर आगे बढ़ेंगे तभी रिपीट करवाएंगे। सरकार रिपीट करने के लिए एफ.सी. मंशा है कि सरकार रिपीट हो। मुझे भरोसा है

## पैसिफिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिलचस्पी का कारण वह की समुद्री भू-सम्पदा है।

प्रशांत महासागर में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजी बेड़ों का प्रभुत्व है और चीन यहां पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना चाहता है। चीन ने हाल ही में सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सुरक्षा करार किया है जो उसे यह शक्ति प्रदान करता है कि वह वहां पर चीन के निवेशों की सुरक्षा के लिए किसी उपद्रव को शांत करने को लेकर अपनी सेना भेज सकता है और वाणिज्यिक व सैन्य उपयोग के लिए कोई बन्दरगाह बना सकता है।

फिजी और सोलोमन आइलैंड्स में अमेरिका अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है, लेकिन

वह इस मामले में काफी पीछे है।

जमीनी हकीकत: प्रशांत क्षेत्र के कई द्विपीय राष्ट्र अपने यहां महासागरिकों की प्रतिस्पर्धा का स्वागत करना नहीं चाहते, लेकिन वे जो चाहते हैं और जो चीन फिलहाल वह सबसे अच्छी तरह से उपलब्ध करवा रहा है, वह है उनका लगातार सहयोग और क्षमता निर्माण।

उद्धरण योग्य:- न्यूजीलैंड की मैसे युनिवर्सिटी में सुरक्षा अध्ययनों की सोनियर व्याख्याता अना पावेल का कहना है कि “प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की अस्तरदार उपस्थिति नहीं है।” उनके अनुसार “मुझे हमेशा इसे लेकर अशर्मा होता है कि “वाशिगटन सरकार सोचती है कि प्रशांत क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है जबकि वास्तव में बिस्कुल नहीं है।

## अमित शाह का सौरव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक नये अध्याय की शुरुआत उस समय नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसे आसार एवं अनुमान हैं कि वह शुष्कता इस समय हो सकती है। चुनावों से पहले, चूँकि गांगुली के बारे में इस प्रकार की चर्चाओं ज़ोरों पर थी, इसलिए अन्य लोगों के साथ ही, उनकी पत्नी की भी इंटरव्यू लिया गया था। उन्होंने कहा था कि गांगुली को निश्चित रूप से बहुत सारी अन्य चीजें एवं क्षेत्र पसंद हैं।

लेकिन गांगुली ने इस बात पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वे जो कुछ भी करेंगे, उसे काम के शीर्ष बिन्दु पर ही होंगे, जैसे वे क्रिकेट में घातें हैं। इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि अगर वे भाजपा का हिस्सा बनते हैं, तो गांगुली के कथन एवं उनकी प्रकृति के अनुसार, वे मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारों के सर्वोच्च दावे पर होने चाहिए। गांगुली के प्रति भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस दोनों ही अपना स्नेह दर्शाकर, उन्हें अपनी तरफ लेना चाह रही थी।

यह जानकारी मिलने के बाद की गांगुली को सुनने में कोई समस्या है तथा वे अस्पताल में घातें हैं, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस नर्सिंग होम में उन्हें देखने गई थीं। तृणमूल कांग्रेस भी उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करती आ रही है। लेकिन यह सुस्पष्ट है कि तृणमूल में गांगुली की भूमिका गौण रहेगी। पार्टी का स्वामित्व एवं संचालन ममता बनर्जी के पास तथा इन दिनों उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास है। और इन दोनों ही बिन्दुओं पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

इस प्रकार, अगर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से सौरव गांगुली किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो वह भाजपा ही होगी। यह सोचने का कोई कारण नजर नहीं आता कि टी.एम.सी. में वे किसी सहायक या अधीनस्थ की भूमिका में रहना पसंद करेंगे, जबकि भाजपा उन्हें राज्य के सर्वोच्च उच्चतम पद की

■ **अब यह अधूरा काम पूरा किया जायेगा।**

■ **तृणमूल कांग्रेस व भाजपा, दोनों सौरव को अपनी-अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं, पर गांगुली का झुकाव भाजपा की ओर है। क्योंकि, भाजपा में गांगुली शीर्षपद (मु. मंत्री के पद) तक पहुंचाने की आशा रख सकते हैं, पर, तृणमूल में यह पद ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक के लिये आरक्षित है।**

पेशकश करने को तैयार है। लेकिन इस बात को कम महत्व देना ही उचित है। गांगुली ने अभी तक किसी भी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। लेकिन बी.सी.सी.आई. ने अपनी ओर से ही इस बात से इंकार किया है कि बी. सी.सी.आई. छोड़ने की गांगुली की कोई योजना है।

बी.सी.सी.आई. ने एक बयान में कहा है कि बी.सी.सी.आई. के समक्ष इस समय कई नये कार्यों एवं पहलों की सूची है, जिनमें गांगुली की महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका रहेगी।

## ‘नैशनल ग्रीन...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्थिति पैदा होगी। अधिकारियों के सामने यह मुश्किल खड़ी हो जायेगी कि कौन से आदेश माने जायें। इस प्रकार की स्थिति में, संवैधानिक अदालतें सरकार ट्रिब्यूनलों पर प्रभावी माना जायेगी।